20 साल की सेवा और 50 वर्ष की उम्र पार करने वालों अधिकारियों का मध्य प्रदेश सरकार मूल्यांकन कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती को 30 दिन का समय दिया है। मूल्यांकन का काम सभी विभागों को करना होगा।

अंधाधुंध भूजल दोहन करने पर अब भरना होगा 'पर्यावरणीय हर्जाना'

भविष्य की चिंता ▶ चेन्नई जैसे जल संकट से एनजीटी चिंतित, पेयजल बचाने के लिए बड़ा कदम

उद्योगों के साथ व्यावसायिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डर व खनन क्षेत्र पर निगाह

रूमा सिन्हा, लखनऊ

पूरी दुनिया में चेन्नई पेय जल संकट की गूंज के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को भूगर्भ जल सहेजने की चिंता सताई है। पानी बचाने के पुराने और लचर नियम से आगे बढ़कर देशभर में अवैध तरीके से भूजल दोहन करने वालों पर नकेल कसने का फैसला किया है। तय हुआ है कि बिना मंजूरी के भूजल का बेहिसाब दोहन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए भारी-भरकम हर्जाना देना होगा। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खासकर उद्योगों, व्यावसायिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डर व खनन क्षेत्र को निशाने पर लिया है।

हर्जाना विगत वर्षों में निर्धारित क्षेत्र के उपभोक्ता की ओर से गैर कानूनी ढंग से निकाले गए भूजल की कुल मात्रा के आधार पर वसूला जाएगा। घरेलू उपभोक्ता व संस्थागत क्षेत्र भी अवैध भूजल दोहन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के दायरे में होंगे, जबकि कृषि क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

मसौदे के मुताबिक, व्यावसायिक व औद्योगिक सेक्टर में अवैध भूजल दोहन करने वालों से सर्वाधिक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। खास बात यह है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देश के सभी अधिसूचित अथवा गैर अधिसूचित विकास खंडों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू होगी।

किस पर कितनी क्षतिपूर्ति

- उद्योग, बोतलबंद पानी से जुड़े उद्योग, टैंकर इकाइयां, बिल्डर, होटल, माइनिंग इकाइयां : न्यूनतम एक लाख रुपये
- संस्थागत इकाइयां, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप : न्यूनतम 50 हजार रुपये
- घरेलू उपभोक्ता : न्यूनतम 10 हजार रुपये

जल संरक्षण को लेकर एनजीटी लगातार सख्ती बरत रहा है। फाइल फोटो

भूगर्भ जल की स्थिति से तय होगा जुर्माना : सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना के लिए अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल व सुरक्षित क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति की अलग-अलग दरें तय होंगी।

इस तरह बना मसौदा : सेफ संस्था, विक्रांत तोंगड़, शैलेश सिंह आदि की याचिकाओं पर एनजीटी ने तीन जनवरी को टिप्पणी की थी कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भूजल दोहन के नियंत्रण व संरक्षण में विफल रहा है। लिहाजा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय देश में समग्र भूजल प्रबंधन एवं दोहन के रेगुलेशन की एक ठोस मेकेनिज्म तैयार कर 30 जून 2019 तक ट्रिब्यूनल के समक्ष रखे। साथ ही खुलेआम भूजल का दोहन करने वाले से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने का मसौदा सीपीसीबी 30 जून तक तैयार करे।

कैसे होगी क्षतिपूर्ति : मान लीजिए, सुरक्षित क्षेत्र में स्थापित एक कागज उद्योग की जल खपत प्रतिदिन 6000 घन मीटर है। अगर वह तीन साल से गैरकानूनी ढंग से दोहन कर रहा है तो प्रतिदिन 50 रुपये प्रति घन मीटर भूजल दोहन की दर से 41 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भरेगा।

मंजूरी का इंतजार : एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मसौदे को मंजूरी मिल जाएगी।

पहले यह था नियम : अभी तक उद्योगों, व्यावसायिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डर व खनन क्षेत्र में काम करने वालों को जल दोहन के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति लेनी होती थी। यह प्रक्रिया इतनी लचर थी कि कोई भी उसका पालन नहीं करता था।

एमजे अकबर ने फिर दोहराया, रमानी के लेख में लगाए आरोप झूठे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : यौन शोषण के मामले में पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की जिरह पूरी हो गई। इस दौरान अकबर ने प्रिया रमानी की अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा की गई जिरह का जवाब दिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष अकबर ने कहा कि उन्हें यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सहयोगी रुथ डेविड के लिखे लेख के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा कोई लेख लिखा गया है तो वह इस आरोपों से इन्कार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिया रमानी के खिलाफ उन्होंने चुनिंदा तरीके से मानहानि का मामला नहीं दायर किया है। उन्होंने कहा कि रमानी के ट्वीट और उसकी भाषा आपत्तिजनक और झूठ से भरी थी। रमानी के लेख में लगाए गए आरोप झूठे हैं। पीठ ने जिरह सुनने के बाद इसे अगली सुनवाई को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अक्टूबर 2018 में तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर पर मीटू अभियान में एक के बाद एक कई महिला पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद अकबर ने पद से इस्तीफा देकर पत्रकार प्रिया रमानी पर आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।

पीएनबी को 7200 करोड़ लौटाए नीरव : डीआरटी

पुणे, प्रेट्र/आइएएनएस : ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ने शनिवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों को पंजाब नेशनल बैंक को 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए। नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है।

भारत में नीरव मोदी लगभग 14,000 रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में भी वांछित है। डीआरटी के पीठासीन अधिकारी दीपक ठक्कर ने दो मामलों में पीएनबी के पक्ष में दोनों फैसले सुनाए। ठक्कर के पास मुंबई डीआरटी का भी अतिरिक्त प्रभार है।

पीएनबी ने नीरव मोदी से 7000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया वसूली के लिए जुलाई 2018 में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर डीआरटी ने अब अंतिम फैसला सुनाया है। डीआरटी ने 30 जून, 2018 से 14.30 फीसद ब्याज के साथ रकम लौटाने का आदेश दिया है। ऐसे ही एक मामले में जज ने मोदी को 200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम 27 जुलाई, 2018 से 16.20 फीसद ब्याद के साथ पीएनबी को लौटाने का आदेश दिया है।

डीआरटी के आदेश के बाद पीएनबी के वसूली अधिकारी अगर जरूरत हुई तो नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, हालांकि उसकी अधिकतर संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की जा चुकी है।

नीरव मोदी फाइल फोटो

- नीरव की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है बैंक
- इस समय लंदन की जेल में बंद है भगोड़ा हीरा कारोबारी

बता दें कि लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने नीरव मोदी को इस साल 19 मार्च को गिरफ्तार किया था। नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी मामलों की जांच कर रही सीबीआइ उसे भारत लाने का प्रयास कर रही है। लंदन की अदालत में उसके प्रत्यर्पण की सुनवाई चल रही है।

सांसद नहीं अमेठी की जनता ने 'दीदी' को चुना : स्मृति

जागरण संवाददाता, अमेठी

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचीं। यहां जनता से सीधे संवाद बढ़ाने की कोशिश में उन्होंने सलोन के कांटा गांव से 'दीदी आपके द्वार' मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर लोगों की समस्याएं सुनीं और निस्तारण का भरोसा दिलाया। अफसरों से दो टूक कहा कि जनता को दर्द न होने पाए। अमेठी की जनता ने सांसद नहीं बल्कि दीदी को चुना है।

वह डेढ़ माह में तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने कठौरा में विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस मौके पर तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि हम केंद्रीय मंत्री नहीं स्मृति जी को सांसद के रूप में ही देखेंगे क्योंकि अमेठी अब तक अपने सांसद से वंचित थी। इस पर स्मृति ईरानी ने भावुक भरोसा दिलाया कि अमेठी ने 23 मई को अपना सांसद नहीं, दीदी को चुना है। सांसद का कर्तव्य होता है कि वह विधायक और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र में विकास योजनाओं को क्रियान्वयन करे और मैं यह काम पिछले पांच सालों से दीदी के रूप में कर रही हूं। दीदी आपके द्वार से अब स्मृति जनता के दिलों में अब पूरी तरह से दीदी के रूप में बस चुकी हैं। उन्होंने इसके साथ ही जनता दरबार लगाना भी शुरू कर दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ।

- सलोन के कांटा गांव से 'दीदी आपके द्वार' मुहिम का किया आगाज
- अधिकारियों की मौजूदगी में सुनी लोगों की शिकायतें

जगदीशपुर के कठौरा में जनसभा को संबोधित करतीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जागरण

हेलीकॉप्टर घोटाले में गवाह बने राजीव सक्सेना तलब

नई दिल्ली, एएनआइ : अगस्ता-वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच एजेंसियों ने सक्सेना को अगले सप्ताह जांच में शामिल होने को कहा है। दुबई के इस व्यवसायी को 31 जनवरी को भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि सक्सेना के खिलाफ कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, जिसमें उन पर आइटी और काला धन कानून से जुड़े मामलों के उल्लंघन का आरोप है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया से सक्सेना के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित करने को कहा था। बोर्ड यह पता लगाएगा कि सक्सेना का इलाज भारत में हो सकता है या नहीं। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करेगा।

मान महल में निहारी विरासत की भव्यता

जागरण संवाददाता, वाराणसी

शनिवार को वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा किनारे 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा मान सिंह द्वारा बनवाए गए मान महल में वर्चुअल म्यूजियम का करीब सवा घंटे तक अवलोकन किया। इस दौरान सभी आठ दीर्घाओं के माध्यम से श्रीकाशी विश्वनाथ का डिजिटल दर्शन, गंगा में दीपदान, हवन तो किया ही साथ ही कला-संगीत की थाती से भी रूबरू हुए। वर्चुअल तकनीक से बनी गलियों में घूमने के साथ ही खान-पान, अंदाज और मिजाज देखते हुए बनारस को महसूस किया। इस दौरान पीएम ने कार्यकताओं के साथ संवाद किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद भाजपा ने अपने मूल्यों और आदर्शों से बिना डिगे, बिना हटे भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। देश में आम जनमानस के विश्वास का प्रतीक हम बन सके हैं।

वहीं, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि भाजपा के लिए यह गर्व का क्षण है कि हमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नेतृत्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यकर्ता से देश के शीर्ष पद तक पहुंचे। उन्होंने बूथ प्रबंधन का मंत्र संगठन को दिया और लाखों कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर संगठन की संस्कृति समझाई है। आइए हम सभी सदस्यता पर्व मनाएं और सदस्यता के मामले में अपना ही रिकार्ड तोड़कर नया रिकार्ड बनाएं।

मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं

मोदी ने कहा, मैं अर्थशास्त्री नहीं, मुझे अर्थशास्त्र का 'अ' भी नहीं आता, लेकिन यह जानता हूं कि जब देश में समृद्धि आती है तो हर नागरिक अच्छा जीवन जीता है।

पीएम ने एक वाकया सुनाया। बोले, एक बार अहमदाबाद में एक व्यक्ति पैदल जाते हुए मिला और मुझसे पूछा कि मैं साबरमती जा रहा हूं, सही रास्ते पर तो हूं। मैंने बार-बार उससे कहा कि पैदल जाने में तीन-चार घंटे लगेंगे। वह कहता, बस सही रास्ता बताएं, भले ही पांच घंटे लग जाएं। ऐसे ही यह सरकार सही रास्ते पर है, भले ही लक्ष्यों की प्राप्ति में थोड़ा समय लग जाए।

पीएम ने सुनाया गीत.....

वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है,
उसी से तो मेरे हौसले की मीनार है।
चुनौतियों को देख कर घबराना कैसा,
इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है।
विकास के पथ में परिश्रम की महक है,
यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है।
गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं,
बदलते भारत की यही तो पुकार है।
देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा,
अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। एएनआइ

श्रद्धांजलि...

नई दिल्ली में शनिवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

मानहानि केस में पटना पहुंचे राहुल जमानत के बाद खाया इडली-डोसा

न्यायालय संवाददाता, पटना

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से किए गए मानहानि के मुकदमे में पेशी के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पटना आए। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह इडली-वड़ा खाने एक रेस्तरां पहुंच गए। कोर्ट में राहुल ने कहा कि उनके खिलाफ मनगढंत आरोप लगे हैं।

18 अप्रैल को मोदी ने मानहानि का केस दायर किया था। समन जारी होने के बाद शनिवार को राहुल गांधी दोपहर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। सरेंडर के साथ ही उनकी ओर से जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन ने 10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर उन्हें नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने अब इस मामले में राहुल की ओर से गवाही देने के लिए अगली तिथि आठ अगस्त तय की है। अदालत ने राहुल गांधी को आरोपों का सारांश सुनाया। इसपर राहुल ने आरोपों को गलत और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि सभी आरोप राजनीतिक द्वेष में लगाए गए हैं। राहुल की ओर से पटना उच्च न्यायालय के पूर्व महाधिवक्ता शशि अनुग्रह नारायण, अधिवक्ता बीरेंद्र शर्मा और अधिवक्ता अंशुल ने संयुक्त रूप से बहस की। वहीं, परिवादी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बहस के दौरान जमानत के आवेदन का विरोध नहीं किया। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री मोदी के आरोप हैं कि एक चुनावी सभा में राहुल ने कहा था कि 'मोदी' उपनाम वाला व्यक्ति चोर होता है। राहुल के इस बयान से जनता में उनका मान-सम्मान घटा है। लोग मुझे सशंकित निगाहों से देख रहे हैं।

जमानत मिलने के बाद राहुल कांग्रेस नेताओं के साथ लंच करने मौर्यलोक स्थित बसंत विहार रेस्टोरेंट पहुंचे। खाने में उन्हें आनियन रवा मसाला डोसा, इडली-वड़ा, इडली वड़ा मिक्स, फ्रेश लेमन सोडा, डाइट कोक परोसा गया। खाना खाने के बाद उन्होंने कॉफी ली। खाने का बिल 2100 रुपये आया। बिल का भुगतान करने के लिए उनके निजी सचिव कनिष्क ने वॉलेट निकाला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर दिए। उनकी सेवा में रेस्टोरेंट के करीब एक दर्जन स्टाफ लगे हुए थे। ऐसे में जाते समय राहुल गांधी ने उन लोगों को एक हजार रुपये बतौर टिप दिए। खाने के बारे में पूछने पर कहा कि उन्हें यहां के खाने का स्वाद काफी पसंद आया और मौका मिला तो दोबारा यहां जरूर आना चाहेंगे।

- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, राजनीतिक कारणों से लगाए गए मनगढ़ंत आरोप
- कोर्ट से किया वादा, जमानत मिलने पर न भागूंगा और न ही साक्ष्य के साथ करूंगा छेड़छाड़

पटना में शनिवार को मानहानि मामले में अदालत में पेश होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। एएनआइ

कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए चाहिए युवा नेता : कैप्टन अमरिंदर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का पार्टी अध्यक्ष पद से दिए इस्तीफे पर अड़े रहना निराशाजनक है। यह पार्टी के लिए नुकसानदेह भी है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस कार्य समिति किसी युवा नेता को आगे लाए। अब पुराने नेताओं को नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ने का समय आ गया है। इसके बिना कांग्रेस मौजूदा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकती।

देश में युवाओं की बढ़ रही आबादी का जिक्र करते हुए कैप्टन ने कहा कि किसी ऐसे नेता को आगे लाया जाए जिसकी समूचे भारत में पहचान हो। निचले स्तर पर अपनी मौजूदगी से वह लोगों में उत्साह भर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल ने पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए युवा लीडरशिप को राह दिखाई है। भारत नौजवानों की संख्या में दुनिया में सबसे आगे है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि एक युवा नेता लोगों की उम्मीदों को ज्यादा प्रभावी ढंग से समझ सकता है। पार्टी लीडरशिप में किसी भी तरह की तब्दीली देश की सामाजिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए क्योंकि 65 फीसद आबादी 35 साल से कम उम्र की है। कैप्टन ने कहा कि पार्टी में जोश भरने के लिए कांग्रेस को युवा नेता की जरूरत है जो एक बार फिर से कांग्रेस को देश की पसंदीदा पार्टी बना सके। पार्टी की लीडरशिप देश की ख्वाहिशों को अपनी सोच में शामिल करके ही पार्टी का पुनर्निर्माण कर सकती है। पार्टी की बुजुर्ग लीडरशिप के दिशा-निर्देश में दूरदृष्टि और आधुनिक सोच वाला एक नौजवान नेता ही नए भारत के जन्म के लिए रास्ता तैयार कर सकता है जो ज्यादा गतिशील, जोशीला और आगे बढ़ने वाला हो।

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल फोटो

राजनीतिक समीकरण

राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी ने कहा, राजग के दोनों बड़े दलों के आपसी संबंध सहज नहीं

भाजपा या जदयू के साथ जाने का प्रस्ताव नहीं आया : तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में नए राजनीतिक समीकरण के साथ राजद की सत्ता में वापसी के कयासों को खारिज कर दिया है। राजद के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को दुविधा की राजनीति से उबरने की सलाह देते हुए तेजस्वी ने साफ कहा कि उनके पास अभी तक किसी भी दल की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। आएगा भी या नहीं, यह भविष्य की बातें हैं।

शनिवार को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि राजग के दोनों बड़े दलों के आपसी संबंध सहज नहीं हैं, लेकिन राजद का उनके साथ जाने की खबर महज अफवाह है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा एवं जदयू के रिश्ते चाहे जितने कड़वे हो जाएं, किंतु हमें राजद को मजबूत करना है। उस तरफ ध्यान नहीं देना है।

राबड़ी देवी, रघुवंश प्रसाद, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव की मौजूदगी में तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की दशा-दिशा और तैयारियों पर भी अपनी राय रखी। राजद में बदलाव की राजनीति का संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि हार से जीत का रास्ता निकलता है। हमें नए तरीके से राजनीति करनी होगी। अतिपिछड़े और दलितों को हर हाल में साथ लेना होगा। तेजस्वी ने हार की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए कहा कि हर कोई लालू प्रसाद नहीं हो सकता है। फिर भी हम आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कमियों को दूर किया जाएगा। स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना होगा। तेजस्वी ने अपने विरोधियों की भी जमकर खबर ली और कहा कि उनकी सब पर नजर है। महीने भर सक्रिय नहीं रहने के बावजूद वह बेखबर नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने इस्तीफे की पेशकश की है। हमें पता है कि ऐसी खबरें कहां से चलती हैं? कौन चलाता है? किस मकसद से चलाता है? जाहिर है, हमारी पार्टी में अनुशासन की कमी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है। हमें यह बात समझनी चाहिए।

राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मां राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव। एएनआइ

तेजस्वी ही होंगे राजद के मुख्यमंत्री प्रत्याशी

राज्य ब्यूरो, पटना : राजद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी के बाद लगाई जा रही अटकलों पर राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने विराम लगा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सर्वसम्मति से तेजस्वी के नेतृत्व में फिर विश्वास जताया है और उन्हें विधानसभा चुनाव में पार्टी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी बताया है। बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में राजद ने साफ कर दिया कि वह अपने सामाजिक सरोकारों और पुरानी पहचान को बरकरार रखेगा।

कह के रहेंगे माधव जोशी